- 19th Year
- Issue: 324
- 07.04.2026 (TUESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का बड़ा दांव, कांग्रेस से बोले-बिल का समर्थन करें

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता):प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी से महिला आरक्षण विधेयक में प्रस्तावित संशोधन का पूर्ण समर्थन करने का आह्वान किया है, जिस पर इस महीने के अंत में संसद के विशेष सत्र में चर्चा होनी है। असम के डिज़रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए। संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को होगा, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने पर चर्चा होगी। मोदी ने उज़्मीद जताई कि इस फैसले को सर्वसज़्मति से मंजूरी मिल जाएगी।

उन्होंने महिला आरक्षण के एजेंडे में कई वर्षों की देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम—जो संसद और असम विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33त्न आरक्षण प्रदान करता है—भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सज़ा में रहते हुए पारित किया गया था। मोदी के अनुसार, इस संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा सांसदों में कम से कम 33 प्रतिशत महिलाएं हों।

उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि वह इस पर राजनीति न करे, बल्कि संशोधन को पूरा समर्थन दे ताकि महिलाओं के पक्ष में सर्वसज़्मति से निर्णय लिया जा सके।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पिछले सप्ताह आरोप लगाया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद सत्र आयोजित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। रमेश ने बताया कि सरकार ने मूल रूप से नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर महिला आरक्षण विधेयक को 2034 के चुनावों से लागू करने की योजना बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसे पहले लागू करने की वकालत कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटें हैं, और प्रस्तावित 50त्न वृद्धि से कुल सीटें 816 हो जाएंगी, जिनमें से लगभग एक तिहाई, यानी 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि मौजूदा महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक संसद में परिसीमन विधेयक के साथ पेश किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी सरकार के विधायी एजेंडे के लिए सभी दलों के समर्थन की अपील की है। उन्होंने एएनआई से कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।

युवा नौकरी के लिए पलायन को मजबूर- प्रियंका गांधी

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को केरल में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और कहा कि योग्यता होने के बावजूद कई युवा राज्य से बाहर नौकरी तलाशने के लिए मजबूर हैं। पेरावूर में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं पिछले एक साल से वायनाड की सांसद हूं और मैं आप लोगों की समस्याओं और संघर्षों को करीब से देखती हूं। मैं देख सकती हूं कि आप सभी ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत की है।प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, वे काफी पढ़े-लिखे हैं। केरल में जब मैं पढ़े-लिखे युवाओं से मिलती हूं, तो अज़्सर उनके पास नौकरी नहीं होती, और अगर होती भी है, तो वह राज्य से बाहर होती है। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को निर्धारित है।

ममता बनर्जी के समक्ष सत्ता विरोधी लहर की चुनौती, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप

कोलकाता ०६/०४ (संवाददाता): आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सज़ारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जो राज्य में टीएमसी के शासन को समाप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। टीएमसी 2011 से सज़ा में है, जबकि भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। 2016 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिर्फ तीन सीटें मिली थीं। हालांकि, 2021 में उसके प्रदर्शन में उल्लेखनीय उछाल आया और वह 77 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी दल बनकर उभरी। 2021 के चुनावों के निर्णायक क्षणों में से एक नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में सुवेंदु अधिकारी द्वारा ममता बनर्जी को हराना था। इस हार के बाद, बनर्जी ने भाबनीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल करके 294 सदस्यीय विधानसभा में अपनी सीट बरकरार रखी। इस बीच, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इज़ेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने पूर्व टीएमसी नेता हुमायूं कबीर द्वारा गठित आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में प्रवेश किया है।

एआईएमआईएम-एजेयूपी गठबंधन से मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में वोट शेयर पर प्रभाव पड़ने की उज़्मीद है। छोटे दलों की मौजूदगी के बावजूद, इस चुनाव को बड़े पैमाने पर टीएमसी और भाजपा के बीच एक सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में एक तीव्र राजनीतिक लड़ाई का मंच तैयार हो रहा है।पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण में पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, बीरभूम, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उज़री और दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिमी बर्धमान, दार्जिलिंग, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और कालिज़्पोंग में मतदान होगा। दूसरे चरण में पूर्वी बर्धमान, नादिया, उज़री और दक्षिणी 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में मतदान होगा।

दिल्ली विस की घटना ने हाई प्रोफाइल परिसरों की सुरक्षा तैयारियों पर प्रश्नचिन्ह लगाया

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): दिल्ली में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रज़्तार कार ने दिल्ली विधानसभा के बाहर लगे सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए परिसर में जबरन प्रवेश कर लिया।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना लगभग दोपहर 2 बजे हुई, जब उज़र प्रदेश नंबर की एक कार गेट नंबर-2 को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। पुलिस के मुताबिक, वाहन तेज और लापरवाही से चलाया जा रहा था। अचानक हुई इस घुसपैठ से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की।

दिल्ली सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि चालक विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और पोर्च के पास एक फूलों का गुलदस्ता रखकर वापस लौट गया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार ने सुरक्षा की कई परतों को पार किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं, इस घटना के बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में संपन्न बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 25 मार्च को भेजे गए एक ईमेल में दावा किया गया था कि परिसर में 16 आरडीएज़्स आधारित आईईडी लगाए गए हैं, जिन्हें विस्फोटित करने की धमकी दी गई थी।

देखा जाये तो लगातार मिल रही इन घटनाओं ने राजधानी के इस हाई-प्रोफाइल परिसर की सुरक्षा तैयारियों पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह घटना महज लापरवाही थी या इसके पीछे कोई साजिश है।

जेपी नड्डा ने फूंका जीत का बिगुल, कहा- एनडीए को मिल रहा अपार समर्थन

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में मजबूत माहौल है। तिनसुकिया में एएनआई से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए को समाज के सभी वर्गों का सर्वसज़्मति से समर्थन मिल रहा है। मोदी जी ने असम में जो काम किया है, असम को जो आशीर्वाद दिया है और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने जमीनी स्तर पर जिस तरह से इसे लागू किया है, असम की जनता उसका स्वागत कर रही है।

असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होंगे और मतगणना 4 मई को होगी। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अपने हितों को प्राथमिकता दी और अपने शासनकाल में असम को विकास से वंचित रखा। भाजपा उज़्मीदवार शिलादित्य देव के समर्थन में होजाई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने जिले में बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने असम को बिजली के मामले में एक आदर्श राज्य बताया और उल्लेख किया कि केंद्र ने पीएम सूर्य घर मुज़्त योजना के तहत सौर पैनल लगाने के लिए 70,000 से 80,000 रुपये उपलज़्ध कराए हैं।

मोदी ने कांग्रेस पर परिवार को प्राथमिकता देने का आरोप भी लगाया। 2026 के असम विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत पर विश्वास जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि होजाई हो, पूर्वी कार्बी आंगलोंग हो या पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, आप हर क्षेत्र से ऊर्जा लेकर यहां पहुंचे हैं। यह माहौल दर्शाता है कि असम ने भाजपा-एनडीए के लिए सबसे बड़ी जीत हासिल करने का निश्चय कर लिया है। हर क्षेत्र का विकास एनडीए की प्राथमिकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने शुरुआत में ही होजाई को एक अलग जिला घोषित कर दिया था। हालांकि, कांग्रेस ने असम को परेशानी में रखा और उसे विकास से वंचित रखा। जब तक कांग्रेस यहां सज़ा में थी, उसने केवल अपने स्वार्थों की रक्षा की।

सुनेत्रा पवार बोलीं-जिंदगी का सबसे कठिन चुनाव, खरगे से की विशेष अपील

मुंबई ०६/०४ (संवाददाता): महाराष्ट्र की उपमुज़्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने 6 अप्रैल को बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और निर्विरोध चुनाव का आह्वान किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की प्रमुख पवार भाजपा के साथ गठबंधन में उपचुनाव लड़ेंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव निर्विरोध कराने के लिए मनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब यह था कि कांग्रेस उज़्मीदवार आकाश विजयराव मोरे को अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए। पवार ने कहा कि प्रफुल पटेल और मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे इस चुनाव को निर्विरोध कराने का अनुरोध कर सकें। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन चुनाव है; ऐसा समय किसी के साथ नहीं आना चाहिए। यह चुनाव सिर्फ मेरा नहीं है; यह बारामती के सभी लोगों का चुनाव है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल पटेल ने उनकी अपील का समर्थन करते हुए बताया कि उन्होंने इस मामले में खर्गे के सहायक को संदेश भेजा था।

पटेल ने कहा कि बारामती चुनावों के लिए हमने सभी दलों के नेताओं से बात करने की कोशिश की। मैं पिछले तीन दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी बात नहीं हो सकी, लेकिन मैंने उनका संदेश उनके निजी सहायक को भेज दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों का समर्थन करे।

दुबई में न संपत्ति, न गोल्डन वीसा, गौरव गोगोई के आरोपों पर सीएम की पत्नी का सीधा जवाब

गुवाहाटी ०६/०४ (संवाददाता):असम के मुज़्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई के उन दावों को खारिज कर दिया है कि उनके या उनके परिवार के दुबई या विदेश में कोई संपज़ि या व्यावसायिक हित हैं। उन्होंने गोगोई को अपने परिवार के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने की चुनौती दी है।6 अप्रैल को ङ्क पर एक पोस्ट में, रिनिकी भुइयां सरमा ने कहा कि मैं आपको सस्पेंस में नहीं रखूंगी और इन हास्यास्पद सवालों का जवाब खुद ही दे दूंगी। ये रहा- न तो मेरा, न मेरे बच्चों का, न ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई व्यावसायिक हित या संपज़ि है। अब आपकी बारी। ज़्या आप बता सकती हैं कि आपकी पत्नी का पाकिस्तान में कोई बैंक खाता है या कभी था? और ज़्या आप उन विवरणों को सार्वजनिक करेंगी?

उन्होंने गोगोई के बदलते दावों की आलोचना करते हुए कहा कि यह भी दिलचस्प है कि 24 घंटे के भीतर ही आप 'मिस्र के पासपोर्ट पर गोल्डन वीजा' के अपने दावे से पीछे हटकर अब 'भारतीय पासपोर्ट' की बात कर रहे हैं। यह घटनाक्रम गोगोई द्वारा ङ्क पर सरमा और उनके परिवार की विदेशी संपज़ियों और पासपोर्ट विवरण से संबंधित पहले के प्रश्नों के बाद सामने आया है। गोगोई ने पूछा था कि हिमंता बिस्वा सरमा को निज़्नलिखित प्रश्नों का उज़र देना चाहिए। ज़्या हिमंता सरमा की पत्नी के पास दुबई का गोल्डन वीजा है? ज़्या गोल्डन वीजा भारतीय पासपोर्ट पर है? ज़्या हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार के किसी सदस्य के पास दुबई में संपज़ि है? ज़्या हिमंता बिस्वा सरमा के परिवार का कोई सदस्य विदेश में व्यवसाय करता है? और ज़्या हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने चुनावी शपथ पत्र में विदेश में अपनी या अपने परिवार की संपज़ि का खुलासा किया है?

उन्होंने आगे कहा कि अगर हिमंता बिस्वा सरमा के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें जांच का स्वागत करना चाहिए। जवाब में, सरमा ने 1989-1990 के सेंट किट्स जालसाजी मामले का जिक्र किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे पर आरोप लगाए गए थे, जो बाद में जाली दस्तावेजों पर आधारित पाए गए। मुज़्यमंत्री ने झूठे दावों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस ने सेंट किट्स मामले में एक बार यही तरीका अपनाया था; वो दिन अब बीत चुके हैं। मनगढ़ंत बातों का कानून के तहत कड़ा विरोध किया जाएगा; मेरी कानूनी टीम पहले से ही काम पर लगी हुई है।

5 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद विवाद और गहरा गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि श्रीमती भुयान शर्मा के पास तीन पासपोर्ट हैं और यह दंपज़ि अपने बेटे के साथ मिलकर अमेरिका में 52,000 करोड़ रुपये का कारोबार करते हैं। श्री शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे श्री खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। यह राजनीतिक विवाद 9 अप्रैल को होने वाले असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सामने आया है। 126 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है और परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

विविध समाचार

अबू सलेम जेल से होगा रिहा? ज़्या है 25 साल की जेल की सज़ा वाला गणित

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): गैंगस्टर अबू सलेम, जिसे 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जेल से समय से पहले रिहाई की कोशिश कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस हफ़्ते बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार उसे 25 साल की सज़ा काटनी होगी - यानी उसे 2030 से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। भारत ने पुर्तगाल को आश्वासन दिया था कि अगर सलेम अपने ख़िलाफ़ लंबित मामलों में दोषी पाया जाता है, तो उसे मृत्युदंड या 25 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। 2015 और 2017 में सलेम को क्रमश: बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या और 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। सलेम किस आधार पर रिहाई की मांग कर रहा है?

4 नवंबर, 1993 को मुंबई बम विस्फोट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर पहली चार्जशीट में अबू सलेम, या अबू सलेम अज़्दुल कयूम अंसारी, को एक फरार आरोपी के रूप में नामित किया गया था। पुलिस ने दावा किया कि सलेम को हथियार ले जाने और छिपाने का काम सौंपा गया था और वह धमाकों की साज़िश से जुड़ा था। उसी साल 12 मार्च को, दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह द्वारा समन्वित एक आतंकवादी हमले में मुंबई में एक दर्जन बम विस्फोट हुए, जिसमें 257 लोग मारे गए। सलेम बम धमाकों के साथ-साथ 1995 में मुंबई के एक बिल्डर जैन की हत्या के मामले में भी वांछित अभियुक्त बना रहा। कहा जाता है कि वह देश छोड़कर भाग गया था और अन्य अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू होने और ख़त्म होने तक फरार रहा।2002 में ही जाँचकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली और सलेम को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हिरासत में लिया गया। कहा गया कि उसने अपना रूप बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद उसके फिंगरप्रिंट के आधार पर उसकी पहचान हो पाई। एक साल बाद, पुर्तगाली सरकार ने 1993 के आतंकवादी हमले सहित भारत में हुए अपराधों में उसकी कथित भूमिका से संबंधित उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों और सबूतों के आधार पर सलेम के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सलेम ने सरकार के आदेश के खिलाफ पुर्तगाल की अदालतों में अपील की और तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने आश्वासन दिया कि उसे मृत्युदंड या 25 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा नहीं दी जाएगी। 11 नवंबर, 2005 को सलेम को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया। उस पर बिल्डर की हत्या और 1993 के बम धमाकों के मामले में मुकदमा चलाया गया। उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (टाडा) की धाराओं के तहत हत्या और आपराधिक षडयंत्र का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की एक जेल में बंद सलेम, निचली अदालत, बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न प्राधिकारियों के दरवाज़े खटखटा रहा है और अपनी रिहाई की तारीख़ मांग रहा है। वह दावा कर रहा है कि उसे एक कैदी को मिलने वाले सभी लाभ, जैसे कि सज़ा में छूट, पाने का हक़ है। सज़ा में छूट, अपराध की प्रकृति और अच्छे आचरण, और विशेष योजनाओं आदि के तहत, जेल की अवधि में की जाने वाली कमी होती है। लेम ने दावा किया है कि जेल में बिताए गए समय के आधार पर, वह 3 साल और 16 दिन की छूट का हकदार है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि वह सितंबर 2002 से पुर्तगाल में हिरासत में था, उसने 25 साल से ज़्यादा जेल में बिताए हैं और उसे 31 मार्च, 2025 को रिहा किया जाना चाहिए था। इन गणनाओं के आधार पर, सलेम ने कई बार पुर्तगाली अधिकारियों को पत्र लिखकर दावा किया है कि उसके प्रत्यर्पण की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उसने महाराष्ट्र कारागार विभाग, राज्य सरकार और अदालतों को भी पत्र लिखा है।

आज से दौड़ेगी भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन

नागपुर ०६/०४ (संवाददाता): महाराष्ट्र को भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है, जो नागपुर के अजनी और पुणे के बीच चलेगी। इसके अलावा, यह राज्य की 12वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। इस नई सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को करेंगे।

इस ट्रेन का संचालन और रखरखाव मध्य रेलवे (सीआर) ज़ोन द्वारा किया जाएगा। यह वंदे भारत ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिससे यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रेन बन जाएगी। इसके 10 स्टॉपेज होंगे और इसकी औसत गति 73 किमी प्रति घंटा होगी, जिससे यह नागपुर और पुणे के बीच सबसे तेज़ ट्रेन भी बन जाएगी। पुणे-अजनी-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन संख्या 26101/26102 नाम दिया गया है, 11 अगस्त से पुणे स्टेशन से और 12 अगस्त से अजनी स्टेशन से अपनी नियमित सेवा शुरू करेगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। यह ट्रेन एक बड़ा बदलाव साबित होगी क्योंकि यात्री राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा, यह उन व्यापारियों, छात्रों और कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद होगी जो नौकरी की मांग के कारण नियमित यात्रा पर जाते हैं। यह ट्रेन वर्धा, बडनेरा, अकोला, शेगांव, भुसावल, जलगांव, मनमाड, कोपरगांव, अहमदनगर और दौंड कॉर्ड लाइन सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

यह कुल आठ डिब्बों के साथ चलेगी जिसमें एक एग्जीक्यूटिव चेयर कार (ईसी) और सात स्टैंडर्ड चेयर कार (सीसी) शामिल हैं - जिसमें 590 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी।

आरएसएस ने पहले 'भारत छोड़ो' आंदोलन और फिर संविधान का विरोध किया-कांग्रेस

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता):कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन की वर्षगांठ पर शनिवार को दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने पहले 1942 में इस आंदोलन और फिर कुछ साल बाद संविधान का विरोध किया था।महात्मा गांधी ने 1942 में ब्रिटिश शासन को हटाने का आह्वान करते हुए आंदोलन शुरू किया था, जिसके परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों ने कांग्रेस के लगभग पूरे नेतृत्व को गिरफ़्तार कर लिया था।रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''8 अगस्त 1942 की रात, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए अपना मशहूर 'करो या मरो' भाषण दिया।''

उन्होंने लिखा, ''9 अगस्त, 1942 की सुबह ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में 6 मई 1944 तक नजरबंद रखा गया। नेहरू, पटेल, आज़ाद, पंत और अन्य नेताओं को अहमदनगर किले की जेल में भेजा गया, जहां वे 28 मार्च 1945 तक कैद रहे।''

रमेश के अनुसार, नेहरू के लिए यह उनकी नौवीं गिरफ़्तारी थी। उन्होंने कहा, ''1921 से 1945 के बीच नेहरू ने कुल मिलाकर नौ साल जेल में बिताए। अहमदनगर जेल में ही उन्होंने अपनी अमर कृति 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' लिखी।

''कांग्रेस नेता ने दावा किया, ''जब पूरा कांग्रेस नेतृत्व जेल में था और पूरा देश आंदोलन की लहर में था, तब आरएसएस ने सक्रिय रूप से 'भारत छोड़ो' आंदोलन का विरोध किया। सात साल बाद, इसी संगठन ने भारत के संविधान का भी विरोध किया।

राजग से गठबंधन नहीं हुआ तो अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे-राजभर

पटना ०६/०४ (संवाददाता):राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उज़र प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में उनका राजग से गठबंधन नहीं होता है तो वह मोर्चा बनाकर अवश्य चुनाव लड़ेंगे, इससे उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मंत्री पद का लालच नहीं है। राजभर ने शुक्रवार को जिले के नवानगर में सुभासपा की एक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में राजग से अलग चुनाव लड़ने पर उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा, हम कहां कह

रहे हैं कि बिहार में गठबंधन नहीं करेंगे, हमारी तो पहली कोशिश यही है कि हम लोग राजग गठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ें।उन्होंने कहा, 2025 में बिहार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यदि गठबंधन नहीं होता है तो फिर मोर्चा बनाकर अवश्य चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे बिहार में अलग चुनाव लड़ने पर राजग से रिश्तों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद का लालच नहीं है।

शिक्षा का मतलब सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना-सिंधिया

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल जीवन निर्माण नहीं है, बल्कि उस जीवन में अर्थ का निर्माण करने और सवाल पूछने की क्षमता विकसित करने में सक्षम होना है।

केंद्रीय संचार मंत्री ने शुक्रवार को कहा , ''शिक्षा का उद्देश्य केवल यह प्रश्न पूछना नहीं होना चाहिए कि 'मैं कैसे सफल होऊं', बल्कि यह भी पूछना होना चाहिए कि 'मैं कैसे सेवा करूं'।''

सिंधिया भोपाल में ब्रिटेन से जुड़े 'श्रूसबरी इंटरनेशनल स्कूल' के 150 एकड़ के परिसर के उद्घाटन के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। दक्षिण एशिया के व्यापार आयुक्त और पश्चिमी भारत में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग ने भी इस अवसर पर आयोजित

कार्यक्रम को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, ''मैं भारत में श्रूसबरी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत के मौके पर शामिल होकर प्रसन्न हूं। यह पारस्परिक विकास पर आधारित भारत-ब्रिटेन की दोस्ती का एक नया अध्याय है।''

उन्होंने कहा, ''पिछले महीने हमारे प्रधानमंत्रियों ने 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035' को मंजूरी दी है। इस नयी साझेदारी से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस दृष्टिकोण में शिक्षा और कौशल विकास पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे आने वाली पीढ़ी को बेहतर मौके मिलेंगे।''

कांग ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ''ब्रिटेन की सदियों पुरानी शिक्षा परंपरा और भारत के नए विचारों को मिलाकर हम युवाओं के लिए विश्वस्तरीय अवसर बना रहे हैं। इससे हमारे युवा आगे बढ़ेंगे और भविष्य को नई दिशा दे सकेंगे।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आप सरकार से जुड़ी चार कैग रिपोर्ट पीएसी को भेजीं

नयी दिल्ली ०६/०४ (संवाददाता): दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के समय के वित्त एवं विनियोग खाता 2023-24 और निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी चार कैग रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास जांच के लिए भेज दिया।

गुप्ता ने कहा कि चार अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से सदन में पेश की गई तीन रिपोर्ट पर पीएसी अपनी सिफारिशें अगले अधिवेशन में देगी। विधानसभा सचिवालय ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

(कैग) की इन रिपोर्टों पर कार्रवाई की रिपोर्ट लोक लेखा समिति के समक्ष पेश करें।

विनियोग खातों पर जारी रिपोर्ट में पाया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 15,327 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए, जिनमें से 8,376.40 करोड़ रुपये समय रहते वापस न किए जाने की वजह से लैप्स (समाप्त) हो गए। वित्त खातों पर पेश कैग रिपोर्ट में 346.82 करोड़ रुपये के लंबित संक्षिप्त आकस्मिक बिल और 3,760.84 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाणपत्र न मिलने पर चिंता जताई गई है।

राजस्व अधिशेष 2022-23 के 14,457 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 6,462 करोड़ रुपये रह गया। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि यदि केंद्र सरकार ने 11,123 करोड़ रुपये पेंशन और दिल्ली पुलिस पर खर्च नहीं किए होते, तो राजस्व अधिशेष, राजस्व घाटे में बदल जाता।

राजकोषीय घाटा 2019-20 के 416 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 3,934 करोड़ रुपये हो गया। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पर जारी कैग रिपोर्ट में पंजीकृत श्रमिकों के आंकड़ों में कमी, कल्याण निधि के कम उपयोग और पंजीकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं का उल्लेख है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 6.96 लाख पंजीकृत श्रमिकों में से केवल 1.98 लाख श्रमिकों का ही आंकड़ा उपलब्ध था।

आपदाग्रस्त उज़रकाशी में फंसे लोगों को निकालने के लिए चार हेलीकॉप्टर तैनात

उज़रकाशी०६/०४ (संवाददाता): उज़राखंड के उज़रकाशी में इस हफ़्ते की शुरुआत में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए चार हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई और भारी तबाही मच गई।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को भूस्खलन और अचानक बाढ़ के बाद तबाह हुए धराली क्षेत्र के कुछ हिस्सों से 729 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। धराली क्षेत्र का संपर्क अब भी कटा हुआ है। जिला प्रशासन ने चार मौतों की पुष्टि की है और 49 लोग अब तक

लापता हैं।उज़राखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के चार हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के पांचवें दिन उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं ताकि जिले के अलग-अलग इलाकों में शरण लिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।शनिवार सुबह एक चिनूक हेलीकॉप्टर ने राहत शिविर में जनरेटर सेट ले जाने के लिए जोलीग्रांट हवाई अड्डे से उड़ान भरी। अचानक बाढ़ के कारण धराली और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है।अधिकारियों के अनुसार, प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए गंगनानी के पास लिज़्चागाड़ में युद्धस्तर पर एक बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य रातभर किया गया ताकि यह अगले 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

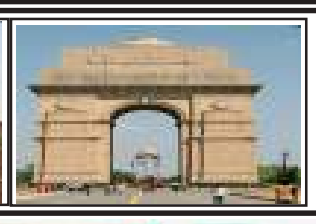

विविध समाचार

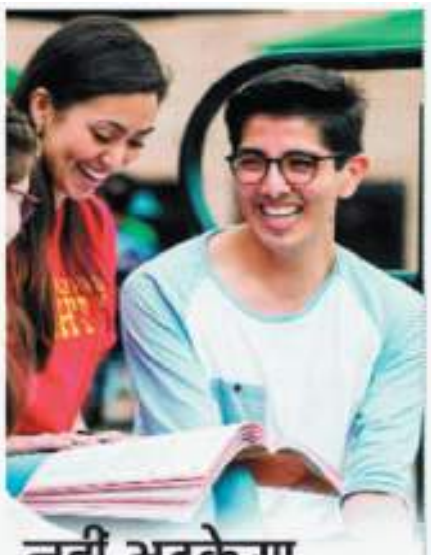

नहीं भटकेगा पढ़ाई से मन, इन टिप्स को अपनाएं

इसमें कोई दो राय नहीं कि पढ़ाई से मन आसानी से भटक जाता है और एकाग्रता की कमी बड़ी समस्या बन जाती है। एकाग्रता यानी आप अपने मन और दिमाग को बाकी चीजों से दूर कर एक समय में एक ही जगह लगाए। लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। आप अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होते ही है। वहीं छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान लगाना और ज्यादा कठिन हो जाता है। इससे तनाव भी बढ़ जाता है। एकाग्रता बढ़ाना बहुत आसान तो नहीं लेकिन अगर आप निश्चय कर लें तो यह संभव है। यहां हम ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिससे आप एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं और किसी भी तरह के तनाव से दूर रहे सकते हैं

- आप मन-मस्तिष्क के लिए आसपास का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए माहौल अच्छा होना जरूरी है जिससे आपका मन भटकने से बचता है। इसलिए यही कोशिश करें कि आप पढ़ाई के लिए आरामदायक और शांतिपूर्ण माहौल चुने।
- पहली बार तो यह है कि अगर आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। इसके लिए पहले से ही अपनी पढ़ाई का खाका तय कर लें। इससे आपके मन में और कोई विचार नहीं आएगा और आपका मन पढ़ाई में लगेगा।
- एकाग्रता में सबसे ज्यादा दखल विचारों की होती है। मन के भटकने का एक कारण विचारों की अधिकता भी है। इसलिए जब पढ़ाई करने समय आपको लगे कि आपके दिमाग में दूसरी चीजें आ रही है तो इस बात को लेकर सजग हो जाएं कि आपको अपना ध्यान नहीं भटकाना है। एक बार आप इस बात को लेकर काशस हो जाएंगे तो एकाग्र होने में मदद मिलेगी।
- अगर आप पढ़ाई के लिए एकाग्र मन चाहते हैं तो जरूरी है कि आपकी स्टडी प्लॉन्ड हो। अगर आप योजना के साथ पढ़ाई करने बैठेंगे तो आसानी होगी। इससे आपकी पढ़ाई और समय के बीच एक अच्छा संतुलन बन जाता है और आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे पाते हैं।
- मन तब ज्यादा भटकता है जब आप एक जगह नहीं बैठते। इसलिए एकाग्र मन के लिए आपको बैठने की एक जगह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। यह दृढ़ हो जाए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना सीट से नहीं उठेंगे।
- बहुत जरूरी है कि आप जहां भी बैठे वो वहां साफ-सफाई होनी चाहिए। अगर वहां बिखराव होगा तो आपका मन भी भटकेगा और ध्यान नहीं लगा पाएंगे।
- एक बहुत जरूरी टिप यही है कि आपको पहले तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अच्छा व्यायाम और पौष्टिक आहार न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है बल्कि आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। इससे शरीर से आलस और थकान दूर होती है।

कजाकिस्तान में सस्ती है एमबीबीएस की पढ़ाई

हर साल भारत का करीब 25 हजार युवा छात्र विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज के एमबीबीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि भारत में काउंसिलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अधिकतर छात्रों, जिनको भारत में सीट नहीं मिलती है वह विदेशी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं।

हर साल भारत का करीब 25 हजार युवा छात्र विदेश की टॉप यूनिवर्सिटीज के एमबीबीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। क्योंकि भारत में काउंसिलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद अधिकतर छात्रों, जिनको भारत में सीट नहीं मिलती है वह विदेशी यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं। लेकिन इस साल भारत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा। जिसके कारण 50 दिन बर्बाद हो गए हैं। वहीं जून-जुलाई में विदेशी यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहती है। वहीं इस साल भी विदेश से एमबीबीएस करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

वहीं बाकी के छात्र एमबीबीएस काउंसिलिंग पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। भारत में आई अनिश्चितता से अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज एडमिशन प्रोसेस की डेट्स में बदलाव नहीं करेंगे। इसलिए भारत में नीट परीक्षा पास कर चुके छात्रों के पास अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वह एमबीबीएस काउंसिलिंग राउंड में हिस्सा लेकर विदेशी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के लिए अपनी सीट आरक्षित करें। इससे अगर आपको भारत में सीट नहीं मिली तो कम से कम आपका साल बर्बाद नहीं होगा और विदेश में एमबीबीएस के लिए सीट मिल जाएगी। क्योंकि कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चीन और रूस आदि देशों में अधिकतर यूनिवर्सिटी सीजा जारी करने से पहले ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं लेतीं।

विदेश में एमबीबीएस

हर मेडिकल स्टूडेंट को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना अनिवार्य है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आप एम्स में पढ़ाई कर रहे हों, या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में या फिर विदेश से स्नातक हों। प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने के लिए सभी डॉक्टरों को भारत में NExT लाइसेंस परीक्षा पास करनी होगी। NMC भारत और विदेश से स्नातक करने वालों को एक समान मानता है। ऐसे में भारत में प्रबंधन/एमबीबीएस सीटों के लिए छात्र भारी फीस क्यों चुकाए। क्योंकि भारत में 1 करोड़ रुपए लागत वाली सीट भी प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस नहीं दे सकती है। ऐसे में यहां पर सरकारी सीट के लिए एमसीसी काउंसलिंग से गुजरने और विदेश में कम फीस वाले शीर्ष रैंक कॉलेज में अपनी सीट आरक्षित करने के ऑप्शन को चुनना चाहिए।

जल्दबाजी में न लें एडमिशन

एडमिशन लेना सिर्फ आधे काम को पूरा करना है। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम के अंत में जब स्टूडेंट वापस भारत आता है, तो उनको FMGE की जगह NExT की परीक्षा देनी होती है। पिछले 10 सालों में लाइसेंस परीक्षा FMGE के रिजल्ट परिणाम साफ दिखाते हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन असल समस्या बाहर निकलने के बाद है। हालांकि स्थानीय सलाहकार छात्रों को सिर्फ एमबीबीएस में प्रवेश प्रदान करते हैं, बाहर निकलने का कोई समाधान नहीं है। ऐसे में आपको उन पेशेवर प्रदाताओं के पास जाने की जरूरत है, तो न सिर्फ आपको एडमिशन दे सकते हैं, बल्कि आपको NExT/USMLE जैसी लाइसेंस परीक्षाओं में मंजूरी की गारंटी भी दे सकते हैं।

कजाकिस्तान की कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी

कजाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, जो भारतीय छात्रों के लिए एकीकृत NExT बैच के कारण भारत में लाइसेंस के लिए गारंटी प्रदान करता है। वर्तमान समय में इस यूनिवर्सिटी में करीब 1,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं यहां पर NExT में 100% उत्तीर्ण अनुपात के साथ ही सफलता की वजह एमबीबीएस कोर्स में एकीकृत 6 साल की NExT कोचिंग है। यह यूनिवर्सिटी पहले साल से ही छात्रों को NExT की तैयारी करवाना शुरू कर देती है। वहीं हर सेमेस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। यूनिवर्सिटी में पहले 150 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप के साथ यह पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है।

बता दें कि अगर आपका नीट स्कोर 500 से कम है, और एमबीबीएस कोर्स का बजट 40 लाख से रुपए से कम है। तो आपको प्लान बी के तहत विदेश से एमबीबीएस करना चाहिए। वरना आप NEET में फिर से एग्जाम देकर अपना एक साल और बर्बाद करेंगे।

आपको किसी ऐसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहिए, जो NExT/USMLE जैसी लाइसेंसी परीक्षाओं के लिए छात्रों को न तैयार करता हो। क्योंकि बिना लाइसेंस के भारत में डॉक्टर बनने की संभावना बेहद कम है। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ या हृदय रोग विशेषज्ञ आदि बनना चाहते हैं, तो आपको शुरूआत से ही USMLE की तैयारी करनी चाहिए।

वर्तमान समय में देखा जाए तो कजाकिस्तान में एमबीबीएस करना सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विकल्प है। आप कजाकिस्तान के शीर्ष रैंक वाले सरकारी कॉलेज कोक्शेताउ स्टेट यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड एनईएक्सटी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पर आप NExT की भी तैयारी कर लेंगे। भारत से पहले 150 आवेदकों को इस यूनिवर्सिटी में NExT कोचिंग निःशुल्क यानी की फी में कराई जाती है। वहीं अगर आपका बजट अधिक यानी की 45 लाख रुपए के आसपास है। तो आप जॉर्जिया में एमबीबीएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में पीजी के लिए जॉर्जिया विश्वविद्यालय में एकीकृत अमेरिकी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जबरदस्त करियर का नया रास्ता, मैनेजमेंट में करें पीएचडी

प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में पीएचडी छात्रों के बीच लोकप्रिय ऑप्शन है। यह एक प्रतिष्ठित डिग्री आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल बेहतर बनाती है। इंडस्ट्री और शिक्षा क्षेत्र में लीडरशिप रोल के लिए इसमें कई बेहतर मौके मौजूद है। अगर करियर में सुधार चाहते हैं तो यह डिग्री आपके लिए सही हो सकती है। बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया में आजकल ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में पीएचडी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कोर्स अपने क्षेत्र के बारे में गहरी जानकारी देता है। अगर आप ऐसे में भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट पीएचडी करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैनेजमेंट में पीएचडी करने के बाद आपके पास बहुत सारे अच्छे जॉब के मौके होंगे। मैनेजमेंट पीएचडी करके छात्र अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, पॉलिसी एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चीफ एक्जीक्यूटिव, ऑफिसर, क्रिएटिविटी एनालिस्ट और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। यह डिग्री आपको पढ़ाने और नौकरी, दोनों ही क्षेत्रों में काम करने का मौका देती है और जॉब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैनेजमेंट पीएचडी कोर्स पूरी दुनिया में मान्य है और आप बड़ी-बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने के लिए योग्य बन जाते हैं। इस कोर्स से आप एक अच्छे विचारक, समस्याओं का हल निकालने वाले, बेहतर निर्णय लेने वाले और कुशल योजनाकार बनते हैं। इसके साथ आप मैनेजमेंट, काम सौंपने, बातचीत करने और मुश्किल व्यावसायिक परिस्थितियों को संभालने में भी माहिर बनते हैं।

बढ़ रही है मैनेजमेंट में पीएचडी की मांग

कोविड-19 महामारी ने दुनियाभर में उथल-पुथल के बाद दुनिया ने ऐसे लीडर्स की जरूरत महसूस की जो मुश्किल समय में भी सही फैसले ले सकें। मैनेजमेंट में पीएचडी से न सिर्फ छात्र, बल्कि उन कंपनियों को भी फायदा मिलता है जिन्हें अनिश्चित समय में नेतृत्व करने वाले कर्मचारियों की जरूरत है और नए जमाने की प्रतिभा रणनीतियों को लागू कर सकें।

शोध और नवाचार

पीएचडी प्रोग्राम शोध और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। स्टूडेंट्स को नए विचारों पर काम करने, नई रणनीतियां बनाने के साथ मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपने ज्ञान का योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आज के समय की व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने और प्रगति करने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है।

शैक्षणिक संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच सहयोग

ज्यादातर मैनेजमेंट पीएचडी प्रोग्राम शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग पर जोर देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को प्रैक्टिकल जानकारी और असल दुनिया का अनुभव दोनों मिलें, जिससे उनकी रिसर्च प्रासंगिक और प्रभावशाली बने। इससे थ्योरी ज्ञान और प्रैक्टिकल उपयोग के बीच की खाई को पाटने में भी मदद मिलती है।

क्या पीएचडी करना आपके लिए सही है?

पीएचडी में दाखिला लेने से पहले, यह सोचने की जरूरत है कि क्या यह आपके करियर के लक्ष्यों के हिसाब से सही है। पीएचडी प्रोग्राम काफी कठिनाई भरे हो सकते हैं। इसके लिए पूरी लगन और रिसर्च के प्रति जुनून की जरूरत होती है। अगर आप हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहने और करियर को आगे बढ़ाने में यकीन करते हैं, तो मैनेजमेंट में पीएचडी आपके लिए सटीक कदम है। मैनेजमेंट में पीएचडी धीरे-धीरे छात्रों के बीच लोकप्रिय हुआ है। यह प्रतिष्ठित डिग्री आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल को बेहतर बनाती है। आज के समय में, जब कंपनियां अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों की तलाश कर रही हैं, तब यह डिग्री अच्छी नौकरियां व करियर में तरक्की दिलाने में सक्षम है।

नई टेक्नोलॉजी के आने से तेजी से विकसित हुई है भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री

भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसे देश के सबसे पुराने इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। भारत में पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने से यह तेजी से विकसित हुई है।

किसी भी देश व सभ्यता के विकास में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। भारत में भी यह इंडस्ट्री देश की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसे देश के सबसे पुराने इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। भारत में पहले सिर्फ फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के आने से यह तेजी से विकसित हुई है। अब यह इंडस्ट्री रिसर्च, डेवलपमेंट, मेन्युफैक्चरिंग और मर्केंडाइजिंग जैसी कई श्रेणियों में काम कर रही है। जिसके कारण इसमें जॉब के अवसर भी पहले की अपेक्षा अब तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में रंग, वस्त्र फाइबर, मशीनरी और उत्पाद, कपड़ा और परिधान प्रक्रियाओं को डिजाइन और नियंत्रित करने की प्रक्रिया शामिल है। जिसमें फैशनेबल कपड़ों की मांग को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज्यादा रिसर्च, क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत होती है। इसमें टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की वह शाखा उन सिद्धांतों का भी अध्ययन करती है जो कपड़ा फाइबर के निर्माण में पॉलिमर का विश्लेषण करते हैं। जिनका उपयोग सभी प्रकार के यार्न और टेक्सटाइल कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। कपड़ा इंजीनियरिंग में, कपड़े को आकर्षक और फैशनेबल बनाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए टेक्सटाइल इंजीनियर को काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। टेक्सटाइल इंजीनियर को नवाचार, अनुसंधान और रचनात्मकता जैसे कौशल की आवश्यकता होती है।

किस तरह का कोर्स करें

अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 12वीं में फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जैसे विषय में पढ़ाई करनी होगी। इसके बाद टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बीई या बीटेक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बीए, टेक्सटाइल डिजाइन में बीएससी, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में बीटेक कर सकते हैं। वहीं आप इन कोर्सेज में एडवांस्ड डिप्लोमा, एमई/एमटेक और उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं।

जॉब प्रोफाइल क्या है

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कई जॉब प्रोफाइल पर रहकर कार्य कर सकते हैं। जिसमें मुख्य रूप से प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोसेस, सेल्स, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, सुपरविजन आदि डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। एक टेक्सटाइल इंजीनियर आम तौर पर इंजीनियरिंग प्रोसेस से जुड़ा होता है, जबकि अपैरल और गारमेंट्स की डिजाइनिंग और मेन्युफैक्चरिंग के लिए काम करने वाले प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर कई स्किल का होना जरूरी है। जिसमें मुख्य रूप से कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्प्यूटर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी जरूरी हैं। इसके अलावा उनमें चीजों की बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी होनी भी जरूरी है।

करियर की संभावनाएं

इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं है। कोर्स पूरा होने के बाद आप टेक्सटाइल मिल्स, एक्सपोर्ट हाउसेज, निटवियर मेन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा निजी सिल्क, हैंडलूम, जूट, खादी, क्राफ्ट डेवलपमेंट संस्थानों में काम कर सकते हैं। आप फैशन डिटेलर्स डिजाइन स्टूडियोज और बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे में भी काम कर सकते हैं।

सैलरी

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्री के बाद आप फ्रेशर के तौर पर अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो 30 से 45 हजार रुपये का शुरुआती वेतन आसानी से मिल जाता है। अनुभव के बाद, आप प्रति माह 50 हजार से एक लाख तक कमा सकते हैं। अगर आपने आईआईटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो आपको शुरुआती वेतन काफी आकर्षक लग सकता है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

मंगलवार 07 अप्रैल 2026

श्रम संहिताएं शोषण का नया औजार

केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर चार श्रम संहिताएं लागू कर दी हैं। इनमें से मजदूरी संहिता 2019 में संसद ने पारित की थी। अन्य तीनों संहिताएं सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 में संसद में पारित की जा चुकी हैं। लेकिन इसके बाद इन्हें लागू करने पर कोई बात नहीं हुई, तो समझा गया कि इन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2024 में मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। फिर चुनाव में जीत कर नरेन्द्र मोदी ने तीसरा कार्यभार संभाला, उसके बाद भी इन श्रम संहिताओं पर कोई बात नहीं हुई। अब यकायक मोदी सरकार ने इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर सबको चौंका दिया। सरकार इस फैसले को कर्मचारियों और मज़दूरों के हित में बता रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू कर दिए हैं। यह आज़ादी के बाद मज़दूरों लिए सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक है। यह हमारे कामगारों को बहुत ताक़तवर बनाता है। इससे नियमों का पालन भी काफ़ी आसान हो जाएगा और यह ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने वाला है। अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है प्रधानमंत्री ने इन्हें आजमाए बिना ये तो कह दिया कि ये मजदूरों के सबसे प्रगतिशील सुधारों में से एक हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले कार्यकाल में इन सुधारों को लागू करने से उन्हें किसने रोका था और अब अचानक इन्हें लागू क्यों किया गया। ध्यान रहे कि जिस समय इन संहिताओं को पारित कराया गया, वह कोरोना महामारी का दौर था। जिसने नोटबंदी के बाद त्रस्त जनता की कमर बुरी तरह तोड़ दी थी। लाखों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए थे। तब नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लुभावना नारा दिया था। अभी श्रम संहिताओं को लागू करते वक्त फिर इसी आत्मनिर्भर भारत की बात ही कही जा रही है। मगर मजदूर संगठन अब भी यह नहीं मान रहे हैं कि इनसे मजदूरों का भला होगा। पांच साल पहले भी उन्होंने इसका विरोध किया था, और वे अब भी यही कह रहे हैं कि यह पूंजीपतियों के हितों को देखते हुए बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मज़दूरों से जुड़े 29 मौजूदा क़ानूनों को 4 कोड में री-पैकेज किया गया है। इसका किसी क्रांतिकारी सुधार के तौर पर प्रचार किया जा रहा है, जबकि इसके नियम अभी तक नोटिफ़ाई भी नहीं हुए हैं। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, %लेकिन क्या ये कोड भारत के मज़दूरों की न्याय के लिए इन 5 ज़रूरी मांगों को हक़ीक़त बना पाएंगे? एसआईआर पर नया विवाद 1.मनरेगा समेत पूरे देश में हर किसी के लिए 400 रुपये की न्यूनतम मज़दूरी 2. राइट टू हेल्थ क़ानून जो 25 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज देगा 3. शहरी इलाक़ों के लिए ए प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 4. सभी असंगठित श्रेत्र के मज़दूरों के लिए पूरी सोशल सिक्योरिटी, जिसमें लाइफ़ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस शामिल है। 5. प्रमुख सरकारी क्षेत्रों में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी पर रोक। देखना होगा कि मोदी सरकार इन सवालों के जवाब देती है या इन्हें अनदेखा कर देती है। वैसे सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मज़दूरी की गारंटी मिल सकेगी और हर पांच साल में न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा की जाएगी। लेकिन जिस देश में साल में कई बार महंगाई के झटके लगते हैं, वहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए पांच साल क्या ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। सरकार का यह भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों को समान मेहनताना मिल सकेगा। एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी और यह सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिहाज़ से काफ़ी अहम होगा। एसआईआर की समय सीमा में संशोधन अच्छी बात है कि इन संहिताओं में इस तरह के प्रावधान हैं, लेकिन महिलाओं को समान वेतन के साथ ही रात में काम के लिए बुलाने की भी छूट दी गई है। बेशक इसमें महिलाओं की सहमति जरूरी होगी, लेकिन इसके बावजूद महिला शोषण के खतरे बढ़ जाएंगे।

बिहार पर भाजपाई जीत का मतलब

अरविन्द मोहन

नतीजों के गणित से भाजपा भले सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सीटों का सबसे ज्यादा लाभ जदयू को हुआ और चुनाव पूरी तरह नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया।

लेकिन नतीजे आते ही भाजपा बिहार जीतती लग रही है। सरकार पर उसके दबदबे से लेकर विपक्ष के ध्वस्त होने, जदयू के अंदर उसकी ज्यादा चलने और आगे की राजनीति में पक्ष-विपक्ष में कोई और प्रतिद्वंद्वी न दिखने से भाजपा बम बम है। भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मु यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में अक्सर एक वाक्य कहा करते हैं-बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे।

यह बात वे हिन्दू-मुसलमान ध्रुवीकरण कराने और जातियों में बंटे हिन्दू समाज की जातिगत गोलबंदियों को तोड़ने के लिए कहा करते हैं। लेकिन बिहार विधान सभा के 2020 और 2025 के चुनाव के अनुभव पर यह बात ज्यादा अच्छी तरह लागू होती है। एनडीए नामक गठबंधन तब भी चुनाव में था और नीतीश कुमार भी साथ थे लेकिन राजद के नेतृत्व वाला विरोधी महागठबंधन बस किसी तरह हार पाया- अगर बेइमानी वाले आरोप भूल भी जाएं तो पूरे बिहार स्तर पर वोटों का अंतर मात्र कुछ हजार का था। तब स्पष्ट लगता था कि भाजपा बिहार जीतना चाहती है और नीतीश को किनारे बैठा देना चाहती है।

उसने नीतीश के खिलाफ मीडिया से लेकर मुंहामुंही अभियान चलाया और शासन में ठीक-ठाक काम करके भी उनकी छवि अवांछित बूढ़े वाली हो गई थी। और इस काम में चिराग पासवान की खुली सेवाएं ली गईं जिन्होंने एनडीए में रहते हुए जदयू के सभी उ मीदवारों के खिलाफ लोजपा के उ मीदवार उतारे थे और बुरी पराजय के बावजूद भाजपा से पुरस्कृत हुए।

संयोग ऐसा हुआ कि रिजल्ट ऐसे आये कि नीतीश के बगैर काम नहीं चलने वाला था और फिर उन्होंने जो जो कहा भाजपा ने माना। इस बार एनडीए एक रहा और सेफ रहा। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और मंगल पांडेय के खिलाफ प्रशांत किशोर के आरोपों के बाद पंगु बन गई भाजपा के लिए नीतीश की आड़ रही, चिराग अनुशासित रहे और एनडीए ने भारी जीत हासिल कर ली।

नतीजों के गणित से भाजपा भले सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन सीटों का सबसे ज्यादा लाभ जदयू को हुआ और चुनाव पूरी तरह नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया। लेकिन नतीजे आते ही भाजपा बिहार जीतती लग रही है। सरकार पर उसके दबदबे से लेकर विपक्ष के ध्वस्त होने, जदयू के अंदर उसकी ज्यादा चलने और आगे की राजनीति में पक्ष-विपक्ष में कोई और प्रतिद्वंद्वी न दिखने से भाजपा बम बम है। यह चुनाव उसने बिना नेता, बिना कोई नया सामाजिक आधार जोड़े और सिर्फ संसाधनों तथा प्रबंधन के सहारे जीता। और संसाधनों मे कितना उसका अपना फंड था और कितना केंद्र सरकार का यह भी विवाद का मुद्दा हो सकता है।

और जिस तरह से उसने चुनाव के पहले दर्जन भर योजनाओं में धन बढ़ाकर लोगों को अपनी तरफ मोड़ा वह शैली भी नीतीश कुमार की न थी। जदयू के अंदर भी भाजपा की तरफ रुझान रखने वाले नेताओं का दबदबा बढ़ा है। चुनाव लड़ा तो गया नीतीश कुमार के नाम पर लेकिन ठीक चुनाव से पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही नहीं जदयू नेता ललन सिंह ने भी कह दिया कि नेता विधायक दल में चुना जाएगा। मंत्रालयों के बंटवारे में भाजपा कोटे से ज्यादा लोग मंत्री बने और गृह मंत्रालय पहली बार नीतीश कुमार से छिना।द्यद्यश्च ऋद्भुस्र - बड़ी कंपनियों के मुनाफे के लिए बनाया गया दवा बाजार बिहार के नतीजों को लेकर विपक्ष अब देश और प्रदेश में एक नया ही मुद्दा उठाया जा रहा है-धांधली का। वह कहां तक जाएगा, कितना सही गलत है यह इस आलेख का विषय नहीं है। लेकिन जो साफ दिख रहा है वह यही है कि अब बिहार की सरकार ही नहीं राजनीति की पूरी डोर ही भाजपा के हाथ में आ गई है। और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडेय जैसों को मंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व ने साफ संकेत दिया है कि उसके लिए मनमानी करना ही सबसे कुशल प्रबंधन है।

जिस तरह उसने चुनाव जीता है उसमें यह बात शामिल थी कि प्रबंधन और संसाधन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस बार न जाति का कार्ड चला न संप्रदाय का। और अगर पुराने फार्मूले की अ यस्त राजद या सामाजिक न्याय का नया चैंपियन बनाने में लगी कांग्रेस ने दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जातिगत ध्रुवीकरण करने की कोशिश की तो इस बार उसे भी भाजपा के कुशल रणनीतिकारों ने जंगल राज से जोड़कर यादव राज आने के डर में बदल दिया। यह डर अगड़ों में तो हुआ ही अति पिछड़ा, पिछड़ा(यादव के अलावा), दलितों और मुसलमानों में भी आ गया।

यह नया बिहार है और इसे बनाने का श्रेय भाजपा को दिया जाए न जाए लेकिन इसकी समझ अकेले उसके रणनीतिकारों को थी। बिहार में विकास की बयार बहती हो ऐसा नहीं है पर वह मण्डल-कमंडल की राजनीति से आगे आ चुका है यह कहने में हर्ज नहीं है। और इसकी समझ ज्यादातर राजनैतिक पंडितों को नहीं थी।

इसी मामले में प्रशांत किशोर थोड़े अलग हैं लेकिन उनकी चुनावी लड़ाई की कमियों के बारे में बहुत कुछ कहना पड़ेगा। उन्होंने भी नई राजनीति की जमीन बनाने में एक भूमिका निभाई है। भाजपा की खूबी यह है कि सत्ता में होते हुए और संघ जैसे जड़ संगठन के साथ रहते हुए भी उसने मजे से अपने अंदर बदलाव किया।

हिन्दुत्व का कार्ड मद्धिम पड़ता गया है और मोदी का मैजिक(जिनमें झूठा स्वर्ग दिखाने का खेल शामिल था) टूटते जाने के साथ उसने शासन और डायरेक्ट डिलीवरी का ऐसा दो आधार अपनाया है कि विपक्ष और उसकी सरकारों को दिक्कत होने लगी है।मु य विपक्षी कांग्रेस समेत सारे विपक्ष को सचमुच बहुत कुछ नहीं सूझ रहा है। और कुछ न हो तो वोट चोरी या ईवीएम का मुद्दा उठाते रहने से उस सवाल का महत्व भी कम हुआ है।

बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर यही किया जा रहा है। संयोग से बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी चल रहे गहन मतदाता सर्वेक्षण में दिख रही कमजोरियों और विपक्ष के मजबूत दलों के भी शोर मचाने से यह मुद्दा जिंदा है। पर कांग्रेस और विपक्ष 2024 के लोक सभा चुनाव में मिले बेहतर परिणामों के बाद जिस कदर चुप रहा है और बिखरा है उसमें बिहार चुनाव नरेंद्र मोदी और भाजपा की राजनीति को चमकाएंगे क्योंकि अभी तक कभी हाथ न आया बिहार अब उनके हाथ आ गया है।

फिर जिन राज्यों में कांग्रेस या विपक्ष की सरकारें हैं वहां शासन में साल-सवा साल में कुछ नया न कर पाने से भी 2024 में मद्धिम पड़ी मोदी राजनीति को लाभ हुआ है। बिहार के धक्के के बाद विपक्षी कैसे संभलता है और मोदी जी उसका कैसा उपयोग करते हैं इस पर सबकी नजर है। वे बंगाल की तरफ बढ़ने का इशारा लगातार दे रहे हैं। बंगाल में विपक्षी एकता शून्य है लेकिन तृणमूल ने अकेले भाजपा को बाहर रखा है। देखना है कि अब कैसी लड़ाई होती है।

केंद्र की श्रम संहिताएं करती हैं मज़दूरों की सुरक्षा को कमज़ोर

नीलोत्पल बसु

कोई प्रौद्योगिकी को उत्पादन की प्रक्रिया में एक ज़रूरी चीज़ मानता है, तो आज इसका इस्तेमाल सिफ़ पूंजी के साथ हो रहा है। एक तरफ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कामगारों को बराबर सुरक्षा न मिलने से शोषण ज़रूर बढ़ेगा। लेबर कोड का हर नियम इसी तरफ इशारा करता है। हार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बड़ी चुनावी जीत और उसके साथ हुई खुशी के तुरंत बाद भारत सरकार ने चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को अधिसूचित कर दिया है। मज़दूरी, औद्योगिक संबंध, काम से जुड़ी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बनी ये संहिताएं देश के %29 श्रम कानूनों को आसान बनाने% के नाम पर हावी हो गए हैं।

नौकरी की सुरक्षा के सवाल पर, श्रम विभाग की सभी संभावित भूमिकाएं खत्म कर दी जाएंगी। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 90प्रतिशत कार्यबल को सभी सुरक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास नियुक्ति का अधिकार (अपॉइंटमेंट अथॉरिटी) नहीं है। केंद्र सरकार का दावा है कि लेबर कोड सभी के लिए न्यूनतम मज़दूरी पक्का करेंगे। लेकिन, कई राज्यों को मौजूदा न्यूनतम मजदूरी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और स्कीम वर्कर्स समेत लाखों कामगार न्यूनतम मजदूरी से बाहर हो जाएंगे, न्यायपूर्ण (फेयर) या लिविंग वेज(जीव चलाने के लिए जरूरी मजदूरी) की तो बात ही छोड़ दें।

यह भी दावा किया जा रहा है कि लेबर कोड्सगिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा लाएंगे। लेकिन, इसके लिए कोई फंड देने या कोई समयसीमा नहीं है। लेकिन नियोक्ता-कामगार संबंध का कई ज़िक्र के बिना, आधार आधारित व्यवस्था वर्तमान कार्यबल के लिए स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करेगा? एक और दावा यह है कि नये लेबर कोड के अनुसार %निश्चित समय के लिए रोजगार% से बराबर फायदे पक्के होंगे। सच तो यह है कि यह सिर्फ स्थायी और कोर जॉब्स में स्थायी रूप से अस्थायी स्थिति लाएगा, और सभी स्थायी नौकरियों को अल्पावधि ठेके वाले कार्य से बदल देगा। इससे सर्विस की निरंतरता, वरीयता और असली फायदों का नुकसान होगा और इसके नतीजे में यूनियन कमजोर होगी।

लेबर कोड सरकार को कंप्लायंस के रक्षक और नियामक की भूमिका से हटाते हैं, शिकायत आधारित निरीक्षण की प्रणाली को ही खत्म कर देते हैं और उसकी जगह स्व-प्रमाणीकरण लाते हैं, जो नौकरी करने वालों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी मौजूदा प्रावधानों को तोड़ने की आजादी का एक नरम शब्द है। एक दावा यह है कि नये लेबर कोड से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), वृक्षारोपण, खनन और विनिर्माण कामगारों की सुरक्षा बेहतर होने की उ मीद है। यह सच से कोसों दूर है। एमएसएमई के कामगार इस कानून के प्रावधानों दायरे से बाहर हैं और सेस उगाही में पारदर्शिता की कोई प्रणाली नहीं है। खनन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों जिनमें दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती हैं, में निरीक्षण कम करने से सिर्फ और ज़्यादा जानलेवा दुर्घटनाएं हो सकती हैं और नियोक्ताओं की ज़ि मेदारी आपराधिकता से मुक्त हो जाएगी।

केंद्र सरकार अपने प्रेस बयान और सोशल मीडिया पर ज़ोर-शोर से कह रही है कि उन्होंने श्रम कानूनों को लेबर कोड से बदलने के लिए कामगारों के साथ हर मुमकिन विचार-विमर्श किया है। आज़ाद भारत में 1966 में बने पहले नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने सरकार, नियोक्ताओं और कामगारों के बीच तीन-तरफ़ा विचार-विमर्श के लिए एक संस्थागत व्यवस्था के तौर पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस (आईएलसी) आयोजित करने की सिफारिश की थी। ज़्यादा जानें प्रादेशिक समाचार साक्षात्कार संग्रह राजनीतिक विश्लेषण पेपर अखबार संपादकीय लेख संग्रह आर्थिक समाचार बुलेटिन ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट बजट 2019 विश्लेषण राजनीतिक चर्चा मंच हालांकि, पिछले दस सालों में आईएलसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी।

इसलिए, जब संसद ने बिना किसी ज़रूरी चर्चा या बहस के लेबर कोड को पारित किया गया, तो यह असल में केंद्र सरकार का एकतरफ़ा हुक्म था, जिसमें मालिकों के अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और कर्मचारियों के सामूहिक अधिकारों और मोलभाव करने की कोशिशों को अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया, और ज़ाहिर है, विरोध करने के अधिकार को भी आपराधिक बनाया गया। वह ठीक वही समय था जब मालिकों की राय कर्मचारियों पर एकतरफ़ा थोपी जा रही थी। यह साफ़ है कि लेबर कोड का असली मकसद ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने में आसानी) को बार-बार एक नारे की तरह दोहराना है। दुख की बात है कि इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि इससे ज़्यादा निवेश आएगा और नतीजतन रोज़गार की दर भी बढ़ेगी। यह उस कड़वी सच्चाई से पूरी तरह अलग है जो सालों से भारतीय उद्योंगों के वार्षिक सर्वक्षणों की रिपोर्टों में सामने आई है। इनसे पता चलता है कि नेट वैल्यू एडिशन में मज़दूरी का हिस्सा लगातार कम हो रहा है, जो 1981-82 में 30.27प्रतिशत से घटकर 2023-24 में सिफ़ 15.97 प्रतिशत रह गया है। इसी दौरान, मालिकों का मुनाफ़ा 23.39 प्रतिशत से बढ़कर 51.01 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रक्रिया का असर कामगारों पर और भी ज़्यादा साफ़ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि दशक की औसत विकास दर 2013-14 में 6.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 4.8प्रतिशत हो गई है। ज़्यादा जानें अर्थजगत समाचार बजट विश्लेषण सेवाएं खेल जगत समाचार साक्षात्कार वीडियो बॉलीवुड समाचार संग्रह प्रादेशिक समाचार अलर्ट युवा केंद्रित सामग्री मनोरंजन समाचार अखबार साक्षात्कार संग्रह ज़्यादा जानें विशेष रिपोर्ट सदस्यता ई-पेपर सदस्यता राजनीतिक विश्लेषण प्रादेशिक समाचार अलर्ट कविता संग्रह पुस्तकें अंतरराष्ट्रीय समाचार युवा विशेष सामग्री बॉलीवुड समाचार संग्रह अर्थजगत समाचार अखबार सरकार मानती है कि बेरोज़गार पढ़े-लिखे युवाओं की सं या बहुत ज़्यादा है।

2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि अगले दस सालों में हर साल औसतन 85 लाख नौकरियां पैदा होंगी, जिसमें भारत में युवाओं की बेरोज़गारी दर दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा 17.6 प्रतिशत है। नीति आयोग का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के आईटी सेक्टर में 20 लाख प्रौद्योगिक नौकरियों पर असर डाल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लेबर ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें लगे लोगों की दशकीय विकास दर, जो 2004-05 और 2013-14 के बीच यह 7.14 प्रतिशत थी, वह 2014-15 और 2023-24 के बीच घटकर 5.92 प्रतिशत रह गयी है। ये आंकड़े साफ तौर पर घरेलू मांग में तेज़ी से कमी की ओर इशारा करते हैं। कॉर्पोरेट्स और नियोक्ताओं पर श्रमिकों का शोषण करने से जुड़ी सभी रोक हटाने से सिफ़ असमानता और बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो घरेलू मांग को पूरी तरह खत्म करने का नुस्खा है।

ऐसी खराब हालत में निवेश कैसे बढ़ सकता है? लेबर कोड असल में मज़दूरों को और गुलाम बनाने का एक ब्लूप्रिंट हैं। वास्तव में, वे आर्थिक उत्पादन के बुनियादी उसूलों को पूरी तरह कमज़ोर करने का संकेत देते हैं, जिन्हें चलाने के लिए दो चीज़ों- श्रम और पूंजी- की ज़रूरत होती है। अगर सरकार नियोक्ताओं पर से सभी नियम हटाकर और श्रमिकों को सब कुछ झेलने के लिए छोड़ कर, दोनों के बीच का संतुलन खत्म कर देती है, तो पूरी उत्पादन प्रणाली टूट और रुक जाएगी। अगर कोई प्रौद्योगिकी को उत्पादन की प्रक्रिया में एक ज़रूरी चीज़ मानता है, तो आज इसका इस्तेमाल सिफ़ पूंजी के साथ हो रहा है।

एक तरफ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन कामगारों को बराबर सुरक्षा न मिलने से शोषण ज़रूर बढ़ेगा। लेबर कोड का हर नियम इसी तरफ इशारा करता है। इसलिए, वे लेबर कोड श्रमिकों के खिलाफ़ एक वर्ग जिहाद बनाते हैं जबकि श्रमबल ज़िंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि मज़दूर मिलकर इसका विरोध करें और इस बुरे सुधार के खिलाफ़ एकजुट होकर संघर्ष करें, जो कॉर्पोरेट मालिकों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाने और हथियार बनाने का एक बहाना है। अच्छी बात यह है कि मज़दूरों की बढ़ती एकता और किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा भी मिलकर इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर सकता है।

बांग्लादेश को खो रहा भारत

चीन बहुत रणनीतिक तरीके से भारत की घेराबन्दी कर रहा है। बांग्लादेश का मामला आश्चर्य के साथ दुखद भी है क्योंकि इसका निर्माण ही भारत की मदद से हुआ था- 1971 में। आज भी वहां से आये लाखों शरणार्थी भारत के नागरिक बनकर सुरक्षित व समृद्ध जीवन जी रहे हैं। भारत सरकार को अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। मोदी की व्यक्तिगत पसंदगी, आकांक्षाओं तथा छवि चमकाने का जरिया बनाने की बजाय उसे देश हित में ढाला जाना चाहिये ताकि दक्षिण एशिया में भारत का वह स मान तथा प्रतिष्ठा बनी रहे जो उसने 2014 में आई भारतीय जनता पार्टी की बनी केन्द्र सरकार के पहले के 60 वर्षों में अर्जित की थी। शुरुआत यहां से करें कि पहली बार जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सभी पड़ोसी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर सभी को चौंका दिया था। उनके इस कदम का स्वागत किया गया था और माना गया था कि वे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे स बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए दक्षेस (सार्क) देशों के सभी राष्ट्रप्रमुख आये थे। इस प्रतिसाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने तथा उसका समझदारीपूर्ण लाभ उठाने के बदले भाजपा के आईटी सेल द्वारा यह प्रचारित किया गया कि पहली बार भारत की ताकत को विदेशी स्तर पर स्वीकारा जा रहा है और इसका कारण मोदी हैं। तत्पश्चात भारत लगातार अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति से हटता चला गया जिसमें व्यक्ति से बड़ा देश को मानने, सामूहिकता तथा छोटे-बड़े सभी देशों की स प्रभुता के स मान का भाव था।

विविध समाचार

भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर वोट चोर–गद्दी छोड़ के नारे लिखे, मामले में तीन गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी

सिरसा ०६/०४ (संवाददाता): सिरसा में कांग्रेस का आज जिला स्तरीय प्रदर्शन वोर चोर गद्दी छोड़ को लेकर होने जा रहा हैं। इससे पूर्व वीरवार रात को कुछ लोगों ने भाजपा नेताओं के पोस्टरों पर काले रंग के पेंट से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लिख दिए। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी वार शुरू हो गई है। भाजपा नेताओं ने पोस्टरों पर काले पेंट से नारा लिखने पर नाराजगी जताई। भाजपा नेता अमन चोपडा ने कहा कि इस तरह की पोस्टरों के साथ हरकत करना निंदनीय है। इसको लेकर वह पुलिस में मामला दर्ज करवाएंगे। बता दें कि ऐसा पहले ही बार

देखने को मिला है। जब इस तरह से किसी प्रदर्शन से पहले स्थानीय व बड़े नेताओं के पोस्टरों पर नारे लिखे गए हो। जनता भवन रोड, बस स्टैंड सहित कई एरिया में इस तरह के नारे पोस्टरों पर देखने को मिले। वहीं, पुलिस ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए शिकायत मिलने के साथ ही जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं के पोस्टरों पर कालिख पोतने के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी दीपक सहारण ने बताया कि घटनाक्रम की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की गई और सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की गई। शहर के अंदर विधायकों और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शन को लेकर पोस्टर लगाए गए है। इन पोस्टरों में जहां विधायकों ने सांसद कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्थान दिया है। वहीं, सैलजा के कार्यकर्ताओं के पोस्टरों से पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो गायब है। कार्यकर्ताओं में अपने अपने नेता के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है या कहें कि कांग्रेस में आपसी फूट अभी भी कायम है जो कहीं न कहीं भरती नजर नहीं आ रही है। भले ही नये जिलाध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। जिलाअध्यक्ष संतोष बैनीवाल भी अभी तक सभी को एक मंच लाने में कामयाब नहीं हुई है।

डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल पर हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, पैरोल पर 1 हफ्ते में लें फैसला

चंडीगढ ०६/०४ (संवाददाता): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की ओर से दाखिल प्रतिनिधि–याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाया जाए। यह याचिका आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि यदि संभव हो तो निर्णय सत्र शुरू होने से पहले लिया जाए और अमृतपाल को इसकी सूचना भी दी जाए। अमृतपाल सिंह ने कोर्ट से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है। फिलहाल वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं। अमृतपाल सिंह ने अदालत के समक्ष यह दलील दी है कि उन्हें छै। की धारा 15 के तहत अंतरिम रिहाई या पैरोल दी जाए ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठा सकें। उन्होंने यह विकल्प भी रखा है कि यदि रिहाई संभव न हो, तो सरकार उनकी संसद में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यक व्यवस्था करे। उन्होंने 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार और अमृतसर के जिलाधिकारी को प्रतिनिधि पत्र भेजकर इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध ा किया था। अब हाईकोर्ट ने इन्हीं पत्रों पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया है।

करीब 19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए अमृतपाल सिंह का कहना है कि उनका संसद में उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानकों के अनुरूप उठा सकें।

रोहतक मंथली प्रकरण : एडीजीपी के गनर सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार, सात अक्तूबर को किया गया था गिरफ्तार

रोहतक ०६/०४ (संवाददाता): मंथली प्रकरण में विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एडीजीपी वाई पूरण कुमार के गनर सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। जल्द अदालत में दाखिल की जा सकती है।

चार्जशीट में अभी सुशील कुमार को ही आरोपी बनाया गया है। पुलिस रिकार्ड के मुताबिक छह अक्तूबर को शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी थी कि वह शराब ठेकेदारी का काम करता हूँ। उसे बड़े बदमाशों जबरन वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है। इस कारण उसे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। हिमांशु भाऊ गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेको में हिस्सा डाला हुआ है।

इस कारण अब जान का खतरा बना रहता है। उसे एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना नाम सुशील बतलाया। बोला आईजी आफिस में मिलने के लिए बुलाया गया है। साथ ही खुद को आईजी का खास आदमी बताया। वह जून माह में आईजी आफिस गया तो वहां पुलिसकर्मी सुशील कुमार ने मुझसे धमकी भरे लहजे में बात की। कहा की अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो मंथली देनी पड़ेगी। नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुझ पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। फिर एक दिन उसका फोन आया की वह काम करना है। उसने लोकेशन भेजकर अपने सेक्टर–एक स्थित कार्यालय में बुलाया। उसने अपने एक साथी जयभगवान को भी बुला लिया। पुलिसकर्मी सुशील ने मंथली के तौर पर ढाई लाख रुपये मांगे। कहा कि आईजी साहब पूरी सपोर्ट करेंगे। पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को एफआईआर दर्ज कर सात अक्तूबर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत के कारण जेल में बंद हैं। रोहतक जेल से उसे अंबाला जेल भेजा जा चुका है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने आरोपी सुशील कुमार के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। अदालत में दाखिल करने से पहले उसे कानूनी एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। ताकि कोई कमी न रह जाए। उम्मीद है शुक्रवार शाम तक जांच टीम अदालत में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अभी अदालत में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। दाखिल करने के लिए चार्जशीट तैयार की जा रही है। जल्द दाखिल किया जाएगा।

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित जालंधर पहुंचने वाले नगर कीर्तन का रूट जारी

जालंधर ०६/०४ (संवाददाता): श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित नगर कीर्तन जालंधर पहुंच रहा है, जिसके रूट की जानकारी जारी कर दी गई है। नगर कीर्तन आज कपूरथला से रवाना होकर करतारपुर पहुंचेगा, जहां से यह वेरका मिल्क प्लांट, नई सब्जी मंडी, वर्कशॉप चौक और कपूरथला चौक से होता हुआ गुरुद्वारा डेरा संतगढ़ साहिब पहुंचेगा। यहां पहले दिन का पड़ाव होगा। अगले दिन, 22 नवंबर को, नगर कीर्तन गुरुद्वारा डेरा संतगढ़ साहिब से कपूरथला चौक होते हुए पटेल चौक, बस्ती अड्डा चौक और भगवान वाल्मीकि चौक तक पहुंचेगा। इसके बाद यात्रा डॉ. बी.आर. अंबेडकर चौक और गुरु नानक मिशन चौक की ओर बढ़ेगी, जहां नगर कीर्तन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। आगे रूट बी.एम.सी. चौक, लडोवाली रोड, पी.ए.पी. चौक (बी.एस.एफ. चौक मार्ग से), रामा मंडी चौक और फिर हवेली पॉइंट तक जारी रहेगा। नगर कीर्तन के स्वागत को लेकर शहर भर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना हुआ है, जबकि प्रशासन ने सुचारू आयोजन के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं।

पंजाब सरकार ने रोपड़ आरटीओ को किया सस्पेंड, शहीदी समागम में बसें मुहैया करवाने में देरी पर हुई कार्रवाई

चंडीगढ़ ०६/०४ (संवाददाता):पंजाब सरकार ने पीसीएस अधिकारी गुरविंदर सिंह को निलंबित कर दिया है। वे वर्तमान में रोपड़ में आरटीओ के पद पर तैनात थे। आरोप है कि गुरु तेग बहादुर के शहीदी समागम में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के लिए आवश्यक बसें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गईं, जिसके चलते सरकार ने यह कार्रवाई की। गुरविंदर सिंह जोहल को पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस अवधि में उनका मुख्यालय चंडीगढ़ निर्धारित किया गया है और वे बिना अनुमति चंडीगढ़ से बाहर नहीं जा सकेंगे।

भागवत की नई दृष्टि और समरत भारत की परिकल्पना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रायः हिंदूवादी संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु वस्तुतः वह केवल एक धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की जीवंत चेतना का प्रतीक है। संघ की मूल प्रेरणा "वसुधैव कुटुम्बकम्" के भाव से उपजी है, जो भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसी दृष्टि का विस्तार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के हालिया बेंगलुरु वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने खुले हृदय से कहा कि "ईसाई और मुसलमान भी संघ में शामिल हो सकते हैं"। यह कथन न केवल साहसिक है बल्कि यह नए भारत, विकसित भारत और संतुलित भारत की सोच का परिचायक भी है। संघ में मुस्लिम, ईसाई समेत किसी भी संप्रदाय के लोगों के स्वागत की भागवत के वक्तव्य की व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह वक्तव्य संघ की व्यापक सोच का भी परिचायक है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुनः पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन–मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह–अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं। यही कारण है कि संघ की दृष्टि में "हिंदुत्व" का अर्थ भारतीयता है अर्थात् भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संवेदना और जीवनशैली से आत्मीय जुड़ाव। ऐसा नहीं है कि इसके पहले संघ में विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, यह अनुमति पहले से है और सच तो यह है कि उसके कार्यक्रमों में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते भी रहे हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। इस सबके बाद भी धारणा यह भी है कि संघ के कार्यक्रमों में केवल हिंदू संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। इस धारणा का कारण यह है कि हिंदू संप्रदाय को लेकर संघ की अपनी विशिष्ट धारणा और परिभाषा है। उसके अनुसार देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू ही हैं, भले ही उनका संप्रदाय और उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ की ओर से बार–बार यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वह सभी को हिंदू के रूप में देखता, मानता और संबोधित करता है। आखिर इस अवधारणा में कठिनाई क्या है? संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, "हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, वह संस्कृति है, जीवन का एक दृष्टिकोण है।" इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व किसी जाति, भाषा, मजहब या सीमित परंपरा का नाम नहीं है। संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या विश्वास से जुड़े हों, इस धरती के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए वे भारतीय हैं और इस दृष्टि से "हिंदू" अर्थात् इस भूमि की सभ्यता के उत्तराधिकारी। संघ की दृष्टि में "हिंदू" शब्द ध ार्मिक पहचान से अधिक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह भारतीय जीवन का पर्याय है, जो समानता, सहिष्णुता और एकात्मता में विश्वास करता है। यही भाव "सर्वे भवन्तु सुखिनः" और "एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति" जैसे मंत्रों में प्रतिध्वनित होता है। आज की राजनीति में समाज को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बाँटने का जो विषवमन चल रहा है, उससे राष्ट्र की एकात्मता को गहरी चोट पहुँच रही है। संघ का उद्देश्य इस विभाजनकारी मानसिकता के प्रतिरोध में खड़ा होना है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य इसी विषहरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, एक ऐसी पुकार जो समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र की आत्मा किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक चेतना में निहित है। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वोच्च देवता है। इस राष्ट्रभक्ति के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि धर्मसम्मतता है अर्थात् ऐसी आस्था जो सभी मतों का सम्मान करती है। इसी भाव से प्रेरित होकर संघ अपने कार्यकर्ताओं को "हिंदू समाज की सेवा के माध्यम से समग्र भारतीय समाज की एकता" का लक्ष्य देता है। भागवत का यह संदेश उस भारत की परिकल्पना करता है जिसमें मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। वे मानते हैं कि "जो भी इस भूमि में जन्मा है, उसका पूर्वज कोई न कोई हिंदू ही रहा है।" यह कथन ऐतिहासिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की सभ्यता का मूल एक ही रहा है, जिसने विविध रूपों में विकसित होकर अनेक धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया। इस संदर्भ में भागवत का दृष्टिकोण गांधीजी की उस संकल्पना से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था– "मेरा हिंदुत्व सबको समेटने वाला है, किसी को बाहर करने वाला नहीं।" यही समावेशी भाव राष्ट्र की एकता का आधार बन सकता है। यदि संघ इस पर बल देता है कि उसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है तो इसका अर्थ यही भी है कि वह सभी भारतीयों को संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकज्पना करता है। कठिनाई यह है कि उसके विरोधी यह प्रचारित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते कि वह तो केवल हिंदू समाज का संगठन है। चूंकि यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संघ के स्तर एवं अन्य स्तरों पर इन देश तोड़क स्थितियों एवं दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण होता रहे। संघ को लेकर फैलायी जा रही यह भ्रांति एवं गुमराह पूर्ण स्थितियों का खुलासा होना जरूरी है कि संघ संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। यदि यह मिथ्या धारणा दूर हो सके तो संघ का कार्य और अधिक आसान एवं सृजनात्मक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि संघ के विरोधी उसके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो भी हो, संघ प्रमुख ने यह कहकर एक तरह से अपने विरोधि ायों और आलोचकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है कि उसके कार्यक्रमों में सभी संप्रदायों के लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल भारत माता के पुत्र के रूप में। उनकी इस पहल का सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग भारत को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या यह किसी से छिपा है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत माता की जय कहने से बचा जाता है?

पिछले दिनों इसी संकीर्ण दृष्टि के कारण वंदे मातरम् के विरोध में स्वर सुनाई दिए। इक्कीसवीं सदी का भारत केवल आर्थिक या तकनीकी महाशक्ति नहीं बनेगा, यदि उसके भीतर मानसिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र न हो।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, मंगलवार 07 अप्रैल 2026

एमसीएल में 35वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया

संबलपुर ०६/०४ (संवाददाता): महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) ने शुक्रवार को गत वित्तीय वर्ष में कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उत्सव मनाते हुए 35वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया. इस अवसर पर कंपनी मु यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसकी शुरुआत उत्कृष्टता दौड़ से हुई। इस कार्यक्रम में सभी निदेशकगण, पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

श्री उदय अनंत काओले, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 'एमसीएल परिवार' को शुभकामनाएं देते हुए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सभी—वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संविदा श्रमिकों—को देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके सतत योगदान के लिए बधाई दी।श्री काओले ने कंपनी के पूर्व नेतृत्वकर्ताओं के उनके मार्गदर्शन एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया7 इसके साथ ही कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, ओडिशा राज्य प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तथा श्रमिक संगठनों को देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एम.सी.एल. को सतत रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया.

इस अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में पूर्व सीएमडी गणों ने कोयला जगत से जुडी विषयों- कोयला मांग, संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की रणनीतियां आदि पर अपने विचार साझा किये, जिसमें मु यालय सहित विभिन्न परिचालन क्षेत्रों के अधिकारी-कर्मचारी एवं ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व सीएमडी श्री ए.आर. शर्मा, श्री एस.एन. शर्मा, श्री एस.आर. उपाध्याय, श्री ए.एन. सहाय, श्री ए.के. झा, श्री आर.आर. मिश्रा, श्री बी.एन. शुक्ला, श्री पी.के. सिन्हा एवं श्री ओ.पी. सिंह सहित श्री केशव राव, निदेशक (मानव संसाधन); श्री पी.के. पटेल, मु य सतर्कता अधिकारी; श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त) तथा श्री एस.के. झा, निदेशक (तकनीकी-ऑप/पीएंडपी) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्टार नाईट कार्यक्रम इस समारोह का मु य आकर्षण रहा, जिसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक, पद्मश्री सोनू निगम ने लाइव कॉन्सर्ट में अपनी शानदार प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया।

कदमटोला गाँव में सामुदायिक केंद्र बनाने का कार्य शुरू

राउरकेला ०६/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सीएसआर विभाग ने बिसरा ब्लॉक के उड़सू ग्राम पंचायत के तहत कदमटोला गांव में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह के साथ एक और महत्वपूर्ण ढांचागत विकास पहल की, जो आसपास के गांवों के समावेशी विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

मु य महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ एवं सीएसआर), श्री टी. जी. कानेकर बतौर मु य अतिथि स्थल पर मौजूद थे । इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बिभाबसु मल्लिक, उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री आर एस बाड़ा, सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बिनायक जेना, ब्लॉक चेयरमैन, बिसरा ब्लॉक, सुश्री फुलमनी केरकेट्टा, उड़सू ग्राम पंचायत के सरपंच, आरएसपी के अधिकारी, साथ ही स्थानीय ग्रामीण और गांव के बुजुर्ग भी मौजूद थे।

प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र में दो कमरे, एक बड़ा हॉल और एक सामने का बरामदा होगा, साथ ही अंदर बिजली और अन्य संबंधित सुविधाएं भी होंगी। 11 × 10 मीटर के इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण मेसर्स एस. आर. महंती द्वारा लगभग 14 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से किया जाएगा।

ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आधार पर इस सुविधा को लिया गया है और इससे गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक आम मंच के रूप में काम करने की उ मीद है। एक बार पूरा होने के बाद, सामुदायिक केंद्र बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामाजिक समारोहों और कल्याणकारी गतिविधियों जैसी विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे सामुदायिक स बन्ध और मज़बूत होंगे और गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

चोरी और खोए 230 मोबाइल फोन पुलिस ने किया जब्त

भुवनेश्वर ०६/०४ (संवाददाता): ऑपरेशन स्माइल के तहत एक बड़ी सफलता में, अंगुल पुलिस ने 230 खोए और चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए। यह गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के मकसद से शुरू की गई पहल का तीसरा चरण है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैंडओवर के लिए, अंगुल में पुलिस अधीक्षक (स्क्क) के ऑफिस में खोए और बरामद मोबाइल फोन के लिए एक खास डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया था। जिन मालिकों ने पहले अपने फोन गुम या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान उनके डिवाइस मिल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद स्मार्टफोन की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपये है इससे पहले, अंगुल पुलिस ने दो अलग-अलग चरणों में लगभग 45 लाख रुपये के 226 स्मार्टफोन लौटाए थे। इस पहल से, जिला पुलिस ने न सिर्फ नागरिकों को उनकी कीमती संपत्ति वापस दिलाने में मदद की है, बल्कि कानून प्रवर्तन में जनता का भरोसा भी मजबूत किया है। अधिकारियों ने कहा कि खोए हुए डिवाइस का पता लगाने और मोबाइल से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। सेंट्रल रेंज पुलिस ड्ढत्न, सत्यब्रत भोई ने मीडियाकर्मियों से कहा, यह तीसरी बार है जब हम मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप रहे हैं। अंगुल स्क्क ने पहले एक नंबर जारी किया था, जिसके अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी भी खोए या चोरी हुए मामले की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। गौरतलब है कि इससे पहले एक और घटना में, खुर्दा पुलिस ने कम से कम 28 मोबाइल फोन बरामद किए थे जो अलग-अलग समय पर चोरी हुए थे या गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया था। यह हैंडओवर पिछले साल 15 दिसंबर को खुर्दा स्क्क के ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था।

ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गंभीर

राउरकेला ०६/०४ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के हेमगिर थाना अंतर्गत कांधडुड़ा गांव में रविवार की शाम को ट्रेलर की टक्कर से वृद्ध गिर गए। गंभीर अवस्था में उन्हें पहले हेमगिर सरकार अस्पताल फ्रि वहां से बेहतर इलाज के लिए सुंदरगढ़ अस्पताल स्थानांतरित किया गया है। कांधडुड़ा गांव निवासी 60 वर्षीय नंदलाल भोई रविवार शाम को पैदल सड़क पर जा रहे थे तभी कोयला लेकर जा रहे ट्रेलर की टक्कर से उन्हें गंभीर चोट लगी। गांव वालों को इसका पता चलने के बाद वे वहां पहुंचे और उन्हें लेकर हेमगिर सरकारी अस्पताल गए जहां से नंदलाल को सुंदरगढ़ अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद चालक ट्रेलर लेकर फ्ऱार हो गया।

सिमिलिपाल नेशनल पार्क में ड्रग्स की खेती पर शिकंजा, 1.7 करोड़ की फसल नष्ट

सिमिलिपाल ०६/०४ (संवाददाता): पुलिस और वन विभाग के एक जॉइंट ऑपरेशन के बाद संरक्षित सिमिलिपाल नेशनल पार्क के अंदर बड़े पैमाने पर अफीम की अवैध खेती का पता चला है।

खास खुफिया जानकारी के आधार पर, अधिकारियों ने एक साथ मिलकर छापा मारा और 1.70 करोड़ रुपये से ज़्यादा कीमत की अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि यह अवैध खेती नेशनल पार्क इलाके के अंदर काफी गहराई में हो रही थी, जो वन और वन्यजीव संरक्षण कानूनों का घोर उल्लंघन है। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, तुरंत कार्रवाई करने के लिए पुलिस और वन अधिकारियों की एक खास जॉइंट टीम बनाई गई।109 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट जॉइंट टीम ने गोपीनाथपुर गांव में ऑपरेशन चलाया, जो सिमिलिपाल इलाके में आता है। छापे के दौरान, लगभग 109 एकड़ वन भूमि में फैली अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि खेती का इतना बड़ा पैमाना संरक्षित वन क्षेत्र के अंदर संगठित और व्यवस्थित अवैध गतिविधि की ओर इशारा करता है। इस खोज से पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील भूमि के अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं, जिससे वन्यजीवों के आवास और वन संरक्षण प्रयासों को खतरा है ।जशिपुर पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज अफीम की फसल नष्ट करने के बाद, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अवैध खेती के संबंध में जशिपुर पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।

आरएसपी के वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन

राउरकेला ०६/०४ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के वार्षिक निष्पादन समीक्षा एवं पुरस्कार समारोह के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। निदेशक प्रभारी (आरएसपी), श्री आलोक वर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यह समारोह ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के गोपबंधु सभागार में आयोजित किया गया। मंच पर कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन), श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री बिस्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (खान), श्री एम पी सिंह, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएँ), श्री सुदीप पाल चौधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर मु य महाप्रबंधकगण, बड़ी सं या में वरिष्ठ अधिकारी एवं संयंत्र के कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि, प्रत्येक वर्ष नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयोजित यह भव्य वार्षिक आयोजन पिछले वित्तीय वर्ष में संयंत्र की उपलब्धियों का उत्सव मनाता है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक तौर पर कर्मचारियों एवं विभागों के योगदान को स मानित करता है तथा नए वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करता है। कार्यक्रम का शुभारंभ सेल के मु य प्रबंध निदेशक (सीएमडी), श्री अमरेंदु प्रकाश के कार्मिकों के लिए ऑनलाइन संदेश से हुआ।

ओडिशा दिवस और नए वित्तीय वर्ष के शुरुआती अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए, श्री आलोक वर्मा ने पिछले वित्तीय वर्ष में आरएसपी के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। हालांकि, उन्होंने सभी को आत्मसंतुष्ट न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि, जो लोग यह सोचते हैं कि बीते कल के तरीके ही आज के लिए सबसे अच्छे हैं, वे किसी भी संगठन को सबसे तेजी से बर्बाद कर देते हैं। वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को बताते हुए, निदेशक प्रभारी ने कहा कि लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन इन्हें प्राप्त करना संभव है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आरएसपी के लिए नया साल अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात संयंत्र जल्द ही विस्तारण के चरण में प्रवेश करेगा और 9.8 मिलियन टन क्षमता वाला संयंत्र बन जाएगा।

अपने समापन टिपण्णी में, श्री वर्मा ने कहा, हमारी विरासत आसान सफलताओं से नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे निष्पादन से परिभाषित होती है। आइए हम वह टीम बनें जो चुनौतियों के बीच अथक परिश्रम करके आरएसपी के लिए एक नया अध्याय लिख सके ।इससे पूर्व, निदेशक प्रभारी ने अन्य गणमान्यों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री ज्योतिर्मय आचार्य के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम द्वारा 'बंदे उत्कल जननी' की मधुर प्रस्तुति से हुई।

श्री बिस्वरंजन पलई ने वर्ष 2025-26 में संयंत्र के प्रदर्शन पर विस्तृत प्रस्तुति दी तथा विभिन्न क्षेत्रों में आरएसपी की उल्लेखनीय उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। वहीं श्री एम पी सिंह ने वर्ष 2025-26 में ओडिशा खान समूह की खदानों के प्रदर्शन एवं उपलब्धियों के साथ-साथ नए वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी। निदेशक प्रभारी में अन्य गणमान्यों के साथ मिलकर, उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न विभागों और व्यक्तिगत कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर श्री आलोक वर्मा ने वार्षिक व्यवसाय योजना पुस्तिका का भी विमोचन किया। मु य महाप्रबंधक प्रभारी (सेवाएँ) एवं अध्यक्ष (आयोजन समिति), श्री अतिश चंद्र सरकार ने सभा का स्वागत किया, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी (आरसीएल), श्री आर एस शर्मा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ प्रबंधक (आरसीएल), सुश्री खुशबू मिश्रा तथा सहायक प्रबंधक (जनसंपर्क), श्री जॉयदेव मजूमदार द्वारा किया गया ।

टीपी गोपालपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड

(पहले का नाम इ.आर.इ.एस-XXXIX पावर ट्रांसमीशन लिमिटेड़)

104 बी, 191/ए, खारवेल नगर, यूनिट-03, 11 वीं स्ट्रीट, भुवनेश्वर, ओडिशा – 751001

शुद्धिपत्र

टीपी गोपालपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड की पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना (ईआरईएस) -XXXIX के लिए इस समाचार पत्र में **07.03.2025**, **28.03.2025** एवं **06.09.2025** को प्रकाशित सार्वजनिक सूचना के विज्ञापन का शुद्धिपत्र।

तत्वों का नाम: **1)** अंगुल (पावरग्रिड)- गोपालपुर **765** केवी डी/सी लाइन

2) गोपालपुर - गोपालपुर (ओ. पी. टी. सी. एल.) **400** केवी डी/सी (क्वाड) लाइन

क्र. सं.	वर्तमान सूची (07.03.2025 को प्रकाशित)			संशोधित सूची		
	गाँवकानाम	तहसील	जिला	गाँवकानाम	तहसील	जिला
2.	तालमुलसासन,	बनरपाल/ बअँरपाल	अनुगुल / अंगुल	तलमुलसासन,	बनरपाल / बअँरपाल	अनुगुल / अंगुल
4.	पांचगछियाजंगल ब्लॉक(क),सेरमुंडा	नरसिंहपुर/ नरसिंघपुर	कटक	पांचगछियाजंगल (क), सेरमुंड	नरसिंहपुर/ नरसिंघपुर	कटक
5.	अंबिथी, हिंडोल	हिंडोल	ढेंकानाल	अंबिठी, हिंदोल	हिंडोल	ढेंकानाल
6.	मणितरा, बेतारसिंघा, बेतारसिंघा, कांजिया पल्ली	बुगुडा	गंजाम	माणितरा, बेतारसिंग, कांजिआपल्ली,	बुगुडा	गंजाम
7.	रंगमाटिआनलिनक्षापुर, लांडाबाउँश / लांडाबाउँसा, घडागपल्ली, नंदपंडपल्ली, हुमु रीधारामशरणपुर, संतरापुर	छतरपुर/ छत्रपुर	गंजाम	रंगमाटिआनलिनाक्षपुर, लंडाबाउँश, घड़घड़ापल्ली, नंदपंडापल्ली, हमुरीधरमाश्रणपुर, सान्तरापुर	छतरपुर/ छत्रपुर	गंजाम
10.	कमसरगड	जगन्नाथप्रसाद	गंजाम	कमासारगड	जगन्नाथप्रसाद	गंजाम
11.	खैरापल्ली /खैरपल्ली, बलिहटा, सनाउत्सापाडा	कबिसूर्य नगर	गंजाम	खइरपल्ली, बलिहता, सनाउत्सापडा	कबिसूर्य नगर	गंजाम
12.	कर्णजरा/ कर्णजारा, नीलासपुर	खल्लीकोट /खलीकोट	गंजाम	करंजरा/करंजारा, निलसापुर	खल्लीकोट /खलीकोट	गंजाम
13.	बारापल्ली,गोठलीखेत / गोठलीखेटा	पुरुषोत्तमपुर/ पुरुसोत्तमपुर	गंजाम	बरपल्ली/बरपली,गोठिआलीखेटा	पुरुषोत्तमपुर /पुरुसोत्तमपुर	गंजाम
14.	बडपंकलाबाडी, महिरकाना	पोलसरा	गंजाम	बदपंकलाबाड़ी, महीरकणा	पोलसरा	गंजाम
16.	हरीराजपुरउर्फ लंगलकंटा, इंडिपटा, एरंडीपाथर / एरंदीपाथर	गणिआ / गणिया	नयागड़/ नयागढ	हरीराजपुरउर्फ नंगलकंटा, इंदिपटा, एरंडीपथर,	गणिआ / गणिया	नयागड़ / नयागढ.
17.	रायतिधोलमारा / रयतिढोलमारा / रायतिढोलमारा, मैंसिबिंधा, ढोलमारा	खंडपडा / खंडापारा	नयागड़/ नयागढ़	रयतिढोलमरा, मईसिबिंधा, ढोलमरा	खंडपडा / खंडापारा	नयागड़ / नयागढ़
19.	कपागाडु, कसियारी, कराडपलि / कराडपल्ली, बरतइला, कलियाम्बा, घडेइबंध	नुआगाँ	नयागड़/ नयागढ़	कपागडु, कासिआरी, करडापलि / करडापल्ली, बड़तइला, कालीआम्बा, घडेइबंध	नुआगाँ	नयागड़ / नयागढ़
21.	पाइकबांकतारा, पथरापल्ली, कामसरागड़, नथिआपल्ली	ओड़गाँ	नयागड़/ नयागढ़	पाइकबांकतरा, पथरपल्ली, कामासारागड़, नाथिआपल्लि	ओड़गाँ	नयागड़ / नयागढ़

तत्वों का नाम: **II)** गोपालपुर - गोपालपुर (ओ. पी. टी. सी. एल.) **400** केवी डी/सी (क्वाड) लाइन

क्र. सं.	वर्तमान सूची (07.03.2025 को प्रकाशित)			संशोधित सूची		
	गाँवकानाम	तहसील	जिला	गाँवकानाम	तहसील	जिला
3.	बडकुशस्थली	कनिसि	गंजाम	बडकुशस्थली, आलीपुर	कनिसि	गंजाम

तत्वों का नाम: **1)** अंगुल (पावरग्रिड)- गोपालपुर **765** केवी डी/सी लाइन

2) गोपालपुर - गोपालपुर (ओ. पी. टी. सी. एल.) **400** केवी डी/सी (क्वाड) लाइन

क्र. सं.	वर्तमान सूची (28.03.2025 को प्रकाशित)			संशोधित सूची		
	गाँवकानाम	तहसील	जिला	गाँवकानाम	तहसील	जिला
1.	ब्राह्मणियपल्ली	छतरपुर/छत्रपुर	गंजाम	ब्राह्मणीआपल्ली	छतरपुर/छत्रपुर	गंजाम

(इस समाचार पत्र में दिनांक **07.03.2025** एवं **28.03.2025** के उपर्युक्त सार्वजनिक नोटिस के अतिरिक्त पढ़े जाने हेतु)